Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.357
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2503I01S01V13P0016

e-ISSN No. 2394-8426
Special Issue on Scientific Research Mar'25
Issue–III(I), Volume–XIII

# राष्ट्र- राज्य व्यवस्था की चुन्नोतीया

**प्रा. डॉ. अतुल नारायण खोटे**
स्व. पुष्पादेवी पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय रिसोड,
जिल्हा वाशिम. पिन 444506
मो.नं. 9822600427
Email – atulkhote11@gmail.com

**सारांश-**

अब तक के वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन समय से लेकर अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा कि अवधारणा बदलती रही है. प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा कि अवधारणा थी, वह अंतरराष्ट्रीय राजनीती के बदलते हुय परिस्थिती के मुताबिक अपने स्वरूप में बदलाव लाया है. आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा कि अवधारणा है, वह कल किस रूप में रहेगी, स्पष्ट नही कहा जा सकता. यह पूर्णता: स्पष्ट हॉ चुका हैकि राष्ट्रीय सुरक्षा कि अवधारणा आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती से जुडी हुई है.

हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र-राज्य व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है. राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के संकीर्ण नजरिए ने भी इस व्यवस्था की नींव को हिलाया है. मुख्य तौर पर लोगों की भावनाएं है जो कभी-कभी पृथकतावादी दृष्टिकोण रखकर राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करती है. अत: राष्ट्र-राज्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करना भी है और आंतराष्ट्रीय राजनीती में निर्माण हुये वाद – लवाद के माध्यम से सुल्झाने कि जरुरत है.

**कीवर्ड -** राष्ट्र, राज्य, अंतरराष्ट्रीय, वैश्वीकरण, उदारीकरण, रासायनिक हथियार.

**प्रस्तावना-** राष्ट्र-राज्यो का अभ्युदय 14 वी शताब्दी से माना जाता है. इससे पूर्व विशाल साम्राज्य अस्तित्व में थे, जिनका शासक वर्ग आम जनता से अछूता ही रहता था. जनता भी विभिन्न भाषा-भाषी समूह मे विभक्त थी. सामंती व्यवस्था के कारण राजा की शक्ती कमजोर पड गयी थी. हालांकी कुछ राजाओ ने इन सामंतो को अपने अधिन करणे का प्रयत्न किया, किंतु उन्हे अधिक सफलता नही मिली. बाद में कुछ शक्तिशाली शासको का उदय हुआ जो स्वयं को सामंती पकड से मुक्त करणे तथा राष्ट्र-राज्यो को सुपरीभाषित ढंग से स्थापित करणे मे सफल हुए.

राष्ट्र-राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठीण है. कुछ विद्वानो का मानना है कि समभाषी लोग मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते है. लेकिन इस मत को पूर्णतः स्वीकार नही किया जा सकता, क्यूकी इंग्लंड और अमेरिका के लोग अंग्रेजी ही बोलते है. लेकिन दोनो अलग-अलग राष्ट्र है. उधर स्वित्झर्लंड के लोग तीन अलग-अलग प्रकार की भाषाए बोलते है, फिर भी एक ही राष्ट्र है. अतएव हम कह सकते है की राष्ट्र लोगों का एक ऐसा समूह है जो यह महसूस करते है कि वे एक-दुसरे के काफी समान है और अन्य समूह से कुछ भिन्न है तथा इस प्रकार वे अपनी एक ही सरकार और कानून के अधिन रहना चाहते है.

आंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है. जिसका अस्तित्व तो राज्य के निर्माण के साथ ही जुडा हुआ है. जब राज्य का जन्म हुआ होगा तब वह अपने राष्ट्र या राज्य की सुरक्षा चाहता होगा और उसी सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है. जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा चाहता है और उसके लिए प्रयत्न करता है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ती या सुरक्षा चाहता है. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए ही कोई देश, अन्य देशो के साथ विदेशी संबंध स्थापित करता है, संघर्ष करता है, या समझोता करता है, किसी आंतरराष्ट्रीय संघटन का निर्माण करता है या किसी अन्य राष्ट्रीय संघटन का सदस्य बनता है. यह स्वीकार करते हुए हमे थोडीशी हीचक नही होनी चाहिये की वर्साय. की संधी, 1919; राष्ट्रसंघ का निर्माण, 1920 और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, कुछ देश के द्वारा सैनिक संघटना के निर्माण के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षाही केंद्रीय विषय था.

अब तक के वर्णन से स्पष्ट हे की प्राचीन समय से लेकर अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा बदलती रही है. प्रथम विश्व युद्ध के पहिले जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा बदलती रही है. प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा थी वह आंतरराष्ट्रीय राजनीती के बदलते हुए परिस्थिती के मुताबिक अपने स्वरूप मे बदलाव लाया है. आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा है, वह कल किसी रूप मे रहेगी, स्पष्ट नही कहा जा सकता. यह पूर्णतः स्पष्ट हो चूका है की राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती से जुडी हुई है.

**राष्ट्र राज्यव्यवस्था की चुनौतियॉ –**

आधुनिक राष्ट्र-राज्य मैकेयाविली के जमाने से अपनी मजबूत स्थिती कायम करणे लगी है, आज के तमाम राज्य राष्ट्र है और तमाम राष्ट्र राज्य है. ऐसी स्थिती मे यह कहना ही उचित है की आज के सभी राज्य 'राष्ट्र - राज्य' है. इन राष्ट्र-राज्यों के पास कई समसामायिक चुनौतीया है, जिनमे राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाये रखना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है. आज के तमाम राष्ट्र-राज्य इस समस्या से चिंतित है की कैसे राष्ट्र-राज्य के अस्तित्व को कायम रखा जाये.

दुसरे, आज के राष्ट्र-राज्यो को आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से जुझना पड रहा है. सभी राष्ट्र आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए अपनी प्रशासनिक व्यवस्था मे नियोजनात्मक पक्ष पर जादा जोर देने लगे है. इन राष्ट्र को इस्लामिक आतंकवादी चुनौतियों का भी सामना करना पड रहा है. कहना नहीं होगा की आज आतंकवाद ने और इस्लामीक रुप धारण कर आंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजहबी वैमनस्य की दिवार खडी कर दी है.

तीसरे, ' राष्ट्र - राज्य को विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए विकासात्मक एवं आवश्यक आर्थिक कार्यों का भी संपादन करना पड़ रहा है जिसे उनके समक्ष चुनौतियां ही कहा जाएगा.

चौथे, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल गया है, पूरे विश्व का लगाम एक ध्रुविय व्यवस्था के नेतृत्व कर्ता अमेरिका ने अपने हाथों में थाम लिया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्र-राज्यों को अमेरिकी निरंकुशता एवं मनमानेपन जैसी चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है.

पांचवें, अंतरराष्ट्रीय वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के दौर में पूरे विश्व के राष्ट्र-राज्य एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं. आज उदारीकरण का न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रो में भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में राष्ट्र-राज्य को विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बीच तालमेल स्थापित करना पड़ रहा है.

छठे, दुनिया के तमाम राष्ट्र-राज्य जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्या को झेल रहे हैं, जिनका निदान इनके सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है.

सातवा, राष्ट्र-राज्य में पैदा होने वाले आंतरिक विवाद इनके अस्तित्व के लिए चुनौती बने हैं. आपसी संघर्ष उस भावना को ठेस पहुंचाते हैं, जिनके आधार पर इनका सृजन किया गया है.

आठवां, लोगों के चारित्रिक स्तर में गिरावट भी इनके अस्तित्व पर चोट करता है. भ्रष्टाचार की घुन से यह राष्ट्र ग्रसित नजर आते हैं.

अंत में, आज राष्ट्र-राज्य के सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती आणविक एवं रासायनिक हथियारों का खात्मा करना है, आज मानवता का अस्तित्व पल भर में मिट सकता है, जिस भय को समाप्त करना राष्ट्र-राज्य के समक्ष गंभीर चुनौती है. इसके अलावा पर्यावरण व नशाखोरी जैसी समस्या राष्ट्र-राज्य के सामने राक्षसी रूप में विराजमान है.

**निष्कर्ष:-** अंतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्र-राज्य व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है. राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के संकीर्ण नजरिए ने भी इस व्यवस्था की नींव को हिलाया है. मुख्य तौर पर लोगों की भावनाएं है जो कभी-कभी पृथकतावादी दृष्टिकोण रखकर राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करती है. अत: राष्ट्र-राज्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करना भी है.

**संदर्भ-**

1. प्राध्यापक वराडकर, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजकरण.
2. फडिया बि. एल., अंतरराष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. रावत बहादुरसिंह, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व एवं सिद्धांत, प्रतियोगिता दर्पण (मासिक) अप्रैल 2020.
4. अशोक कुमार, राजकीय विज्ञान, उपकार प्रकाशन आगरा, 2000.